VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	Bharat Jai prakash		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	160872
Center	M.N. ~~3~~	Date	3 sept

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss.

(150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

CBI एक केन्द्रीय जाँच एजेंसी है जिसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गयी है CBI, अपनी शक्ति DSPE Act 1946 से प्राप्त करता है

सामान्य ~~सहमि~~ सहमति -

(1) CBI का क्षेत्राधिकार मुख्यतः NCT है

(2) राज्यों में भ्रष्टाचार हेतु जाँच के लिये बार 2 अनुमति न लेनी पड़े, इसलिये राज्य प्रायः general consent प्रदान करते है

सहकारी संघवाद को खतरा

(1) राज्यों द्वारा केन्द्र पर CBI के राजनीतिकरण का आरोप लगाकर general consent

वापस ले ली है। (8 राज्य)

(2) इससे CBI को राज्य से case by case अनुमति लेनी होगी।

(3) भ्रष्टाचार सकपाल में CBI की क्षमता इससे प्रभावित होगी।

SC का निर्णय

(1) SC ने भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच हेतु, general consent को जरूरी नहीं माना है

(2) CBI के राजनीतिक तथा दुरुपयोग के कारण 'govt's puppet' कहा है

CBI तथा अन्य संस्थाओं जैसे- ED, IB के राजनीतिकरण से बचने तथा स्वतंत्र कार्यकाल हेतु पूर्व CJI - रमन्ना ने एक Nodel umbrella Agency का प्रस्ताव, इस दिशा में कारगर हो सकता है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. **(150 words) 10**

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

भारत में 73th एवं 74th संविधान संशोधन के माध्यम से 11th व 12th schedule जोड़कर, स्वशासी निकायों की स्थापना की गयी है जो कि खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं

वित्त के स्रोत -

(1) राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण
(2) केन्द्र द्वारा अनुदान
(3) property tax
(4) public services से आय

समस्याएँ -

(1) वित्त आयोग की राज्य सरकारों को सिफारिशें बाध्यकारी नहीं
(2) property tax के माध्यम से निम्न tax collection
(3) राज्यों द्वारा समय पर वित्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हस्तांतरण नही

(4) संविधान प्रदत्त Rural- 29 तथा urban- 18 विषय हस्तांतरित न करना।

(5) वित्त के सीमित स्रोत

(6) भ्रष्टाचार तथा लीकेज

समाधान -

(1) पानी, बिजली प्रदायगी में Local bodies को प्रोत्साहन (NITI Aayog)

(2) municiple bonds से वित्तीयन

(3) social stock exchange से धन प्राप्ति (eg - पिम्परी चिन्चवाड़)

(4) वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी।

(5) समय पर धन हस्तांतरण

(6) Local cadres की स्थापना

वित्तीय रूप से मजबूत किये बिना, स्वशासी शासन अधूरा है जिसके लिये waste to energy Approach जैसे नवाचारी समाधान समय की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. (150 words) 10
भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

भारतीय संसदीय प्रणाली में कैबिनेट समितियाँ, सरकार द्वारा निर्णय लेने हेतु प्रमुख निकाय है जिसकी स्थापना PM, transaction of business Rules, 1961 के तहत करता है।

वर्तमान में भारत में 8 संसदीय समितियां है।

सामूहिक उत्तरदायित्व -

(1) ~~सब~~ CC के निर्णय से सभी सहमत होते है।

(2) CC के निर्णयों का सभी बचाव करेगे।

(3) विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता

कार्यपालिकिय एकरूपता

(1) कार्यपालिका द्वारा निर्णय लेने

हेतु सर्वोच्च निकाय

(2) कैबिनेट मंत्री, विचार-विमर्श एवं चर्चा कर सामूहिक निर्णय लेते है

<u>समस्याएँ</u> -

(1) PM की केन्द्रीय स्थिति

(2) मंत्रीमंडल के सभी सदस्य शामिल नहीं

(3) त्वरित निर्णय लिये जाते है जिससे चुनौती पैदा हो सकती है

(4) राजनीतिक हितों के कारण प्रायः राजनीतिकरण

समाधान

CC के निर्णयों पर संसदीय नियंत्रण

विचार-विमर्श समितियों का तथा open निर्णय

संसदीय समितियें त्वरित तथा आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेकर राजनीतिक स्थिरता व सहकारी संघवाद सुनिश्चित करती है

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में सरकारी योजनाए तीव्र, कुशल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के साथ-साथ खराब सार्वजनिक खरीद एवं project प्रबंधन की समस्या से ग्रस्त है जिसके लिये सरकार ने National public procurement & project man. policy framework जारी किया है

<u>महत्व</u> (PPPM में सुधार का)

(1) Ease of doing business ↑

(2) सरकारी खरीद की लागत ↓

(3) सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार ↓

(4) खरीददारी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता युक्त माल, बेहतर कीमत पर मिलेगा।

चुनौतियाँ -

① अपारदर्शी नीलामी
② Regulatory cholestrol
③ GeM का प्रभावी रूप से कार्य न करना।
④ सरकार < देशी / विदेशी > के साथ भेदभावकारी नीति
⑤ सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु कुशल श्रमबल का अभाव

समाधान

- GeM को प्रभावी बनाना।
- e-governance को प्रोत्साहन
- integrity Pact लागू करना

सरकारी खरीद में पारदर्शिता हेतु सिविल सोसाइटी की भूमिका को बढ़ाना तथा social Audit को प्रोत्साहित करना समय की जरूरत है।

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. (150 words) 10

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक जवाबदेही, शासन को जवाबदेह बनाकर, पारदर्शिता सुनिश्चित ~~करके~~ करने तथा सुशासन का एक प्रभावी माध्यम है जिसके तहत नागरिक समाज की नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदारी होती है।

संस्थागत बनाने में चुनौतियाँ

① राज्य सरकारों की अनिच्छा
② सिविल सोसाइटी की अपरिपक्वता (उदा० - कैम्पेन्स int. - धर्म परिवर्तन)
③ civil society, 4th front of war बन गयी है। (NSA Doval)
④ पर्यावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव के नाम पर infra project को प्रभावित। (IB - 2-3% GDP)
⑤ सरकारी नियम / कानूनों के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पालन का अभाव (CDI रिपोर्ट -10%)

(6) FCRA के पालन को लेकर समस्याएँ

<u>समाधान</u> -

(1) मेघालय की तरह सभी विभागों में Social Audit अनिवार्य करना।

(2) सभी राज्यों मे social Audit unit की स्थापना करना (CAG रिपोर्ट)

(3) सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन हेतु Lobbying को कानूनी बनाना।

(4) दर्पण पोर्टल पर Compliance प्रोत्साहन

(5) FCRA, FEMA के अनुपालन हेतु प्रोत्साहन।

सिविल सोसाइटी द्वारा सरकार एवं प्रशासन को जवाबदेही बनाने हेतु <u>Social Responsibility कानून</u>, लागू किया जाना चाहिये (अरुणा रॉय - MKSS)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. (150 words) 10

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

NCST की स्थापना, NCSC से भिन्न कर Art - 338 (क) के माध्यम से संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

कार्य:
- ST के विरुद्ध अपराधों की जाँच करना।
- SC/ST Act के क्रियान्वयन में सरकार की मदद
- ST के मामलों में नीति-निर्माण में सरकार को सलाह व सहायता
- स्थानीय लोगों के हितों को प्रोत्साहन

<u>मुद्दे</u> (PSC के अनुसार).

(1) पिछले 5 वर्षों से एक भी रिपोर्ट संसद में नहीं आई है।

(2) उच्च पदों पर रिक्तियाँ

(3) उच्च पदों हेतु कठोर भर्ती मानदंड

(4) NCST का राजनीतिकरण

(5) NCST सदस्यों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव

(6) NCST की समय-समय पर होने वाली बैठकों का अभाव

(7) पर्याप्त बजट का अभाव तथा समय पर funding नहीं

मजबूती के उपाय

(1) समयबद्ध नियुक्ति

(2) अलग बजट आवंटन करना

(3) रिपोर्ट पर चर्चा हेतु संसद में निश्चित समय निर्धारण

(4) सदस्यों में पर्याप्त सहयोग एवं समन्वय → नियमित बैठकें

(5) NCST में सिविल-समाज की भागीदारी को प्रोत्साहन

NCST, स्वदेशी लोगों तथा STs पर climate change, covid-19 के प्रभाव का आंकलन कर सरकार को कल्याणकारी उपायों हेतु नीति-निर्माण में सहयोग कर सकता है।

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. (150 words) 10

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत 8th class तक के छात्रों को पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था है।

उद्देश्य

(1) कुपोषण की समाप्ति

(2) girls students में एनीमिया ↓

(3) नामांकन दर बढ़ाना

वर्तमान स्थिति

(1) MDM → PM-पोषण शक्ति scheme

(2) विद्यालयों में दूध, अंडा, फल वितरण

(3) कुपोषण, child stunting व wasting कम किया है। (NFHS-5 रिपोर्ट)

(4) बच्चों के व्यापक स्तर पर बीमार होने की घटनाएँ।

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समस्याएँ - ① Diet विविधता का अभाव
② खाने की गुणवत्ता निम्न होना
③ जाति, धर्म संबंधी मामलों ने भी स्कीम की प्रभावशीलता कम किया है
④ खाना पकाने वाले, cook को कम वेतन
⑤ खाद्यान्न का लीकेज
⑥ अपर्याप्त बजट
⑦ covid - 19

उपचार - ① खाना पकाने हेतु SOP निर्धारण
② क्षेत्र आधारित Diet menu
③ ग्रामीणों की भागीदारी से गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
④ Cook a permanent Job

MDM में सरकार ने food fortification का लक्ष्य निर्धारित किया है जो SDG 2.0, zero hunger प्राप्ति में लाभदायक रहेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. **(150 words) 10**

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

सतत विकास लक्ष्य, MDG के उत्तराधिकारी के रूप में 2015-30 के लिये अपनाए गये हैं। SDG 4.0, gender समानता की बात करता है जिसके लिये SRHR जरूरी है

SRHR
→ गर्भनिरोधक तक पहुँच
→ WASH तक पहुँच
→ Period Leave

बाधाएँ -
① WASH तक पहुँच का निम्न स्तर
② पितृसत्तात्मक मानसिकता, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी Sanitary pads तक पहुँच का अभाव।
③ गरीबी, भुखमरी का उच्च स्तर
④ कुपोषण (एनीमिया - 52% women)

Scanned By Camera Scanner

(5) निम्न आय/तथा श्रमबल भागीदारी निम्न होना (WLFPR - 25.1%)

(6) स्कूलों में women के अनुकूल infra का अभाव

कदम -

(1) period leave को कानूनी बनाना (eg - zomato ने प्रारंभ)

(2) WASH को मानवाधिकार तथा मूलाधिकार में शामिल करना

(3) food fortification व एनीमिया!!

(4) आशा - वर्कर्स के माध्यम से SRHR हेतु जागरूकता तथा महिला उत्पादकता में महत्व

(5) कार्यस्थल को महिलानुकूल बनाना तथा seperate toilet for girls student in schools

SRHR के माध्यम से अमृतकाल में निर्धारित महिला अधिकार संबंधी प्रगति को प्राप्त किया जा सकेगा।

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. (150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना, 2006 में हुई जिसने विश्व में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

कार्य -

(1) UN के कहने पर, किसी देश में मानवाधिकार हनन की जाँच करना। → श्रीलंका, म्यांमार

(2) मानवाधिकार हनन सिद्ध होने पर, UN को प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करती है

(3) मानवाधिकार संरक्षण हेतु नवाचार प्रोत्साहन तथा राष्ट्रों को सुझाव

(4) राष्ट्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है

Scanned By Camera Scanner

मुद्दे -

(1) राष्ट्रों द्वारा UNHRC के निर्णयों या comments का विरोध करना
eg - भारत द्वारा कश्मीर
- china → वीगर

(2) UNHRC में ऐसे देश, जिनका मानवाधिकार संरक्षण में अच्छा रिकार्ड नहीं है वे भी सदस्य बने हुये है उदा० → पाकिस्तान

(3) funding हेतु west पर निर्भरता तथा USA द्वारा, इजराइल की आलोचना करने पर विरोध करना।

(4) UNHRC का राजनीतिकरण

(5) UNHRC की विश्वसनीयता का अभाव

समाधान → नियुक्ति को सुदृढ़ करना
समाधान → funding में सुधार
समाधान → राजनीतिकरण न करना

UNHRC में सुधार कर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में केंद्रित कर विश्व में UN charter तथा Universal Decl. on human Rights के लक्ष्य प्राप्त किये (जा सकते) है।

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. (150 words) 10
अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

पश्चिम एशिया में भारत की विशाल आबादी, व्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के कारण प्रायः extended neighbourhood की संज्ञा दी जाती है

भू- राजनीतिक महत्व

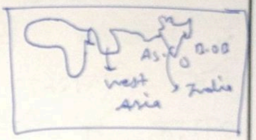

→ चीन का बढ़ता प्रभाव, USA के साथ UAE व सऊदी की भागीदारी।
→ भारत के Israel के साथ संबंधों को पश्चिम एशिया के साथ संतुलित करना
→ UAE + सऊदी v/s Iran
→ I_2U_2 में भारत की भागीदारी
→ हिन्द -महासागर में स्थिति, Piracy से निपटने में महत्व
→ gulf council, OIC का महत्व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ग- आर्थिक महत्व

- भारत के लिये एक बड़ा बाजार (eg - UAE, 3rd partner)
- Remittances का स्रोत, भारत के लिये महत्वपूर्ण (2021-22 - 8 + bn)
- oil & Natural गैस सप्लाई के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा हेतु निर्भरता
- भारत में निवेश का प्रमुख माध्यम
- UAE का वैश्विक व्यापार केन्द्र के रूप में उभरना

हाल ही में प्रस्तावित I2U2 के माध्यम से भारत; USA व इजराइल की तकनीक; UAE का निवेश व भारत का श्रम के माध्यम से व्यापक प्रगति की राह पर जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. (250 words) 15
कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् 'मतदान के अधिकार' का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में 18(+) के व्यक्तियों को 61th संविधान संशोधन के माध्यम से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है फिर भी कैदियों को इससे वंचित किया गया है

वंचन का कारण

① 'मतदान का अधिकार' एक कानूनी अधिकार ना कि मूलाधिकार है

② प्रायः यह माना जाता है कि जो व्यक्ति समाज के लिये खतरा होने के कारण जेल में बंद है वह समाज का नेतृत्व नहीं चुन सकता है

③ मतदान का अधिकार, विधि द्वारा प्रदत्त है जिसे छीना

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी जा सकता है।

प्रभाव –

(1) चुनाव में भागीदारी ↓

(2) under-trial कैदियों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिससे उनकी समस्या बनी रहेगी

अन्य प्रभाव
- Jail Reform नहीं
- Jail में अमानवीय रहने की दशाएँ
- criminal Justice system में सुधार नहीं
- मलिन बस्ति की रिपोर्टिंग नहीं

समाधान –

(1) voting Right प्रदान करना।

(2) भारत में 4.7 Lakh कैदियों की आवाज सरकार तक पहुँचनी चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) समाज में उनकी भागीदारी ↑

(4) पारिवारिक मान-सम्मान ↑

(5) RPA में सुधार द्वारा। election सुधारों के अनुकूल

कानून का अधिकार देकर, undertrials कैदी भी अपनी बात रख सकते है तो साथ ही Jail का उद्देश्य व्यक्ति को सुधारना है ना कि सजा देना।

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. (250 words) 15
भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

भारत और USA दोनों दुनियां के सबसे बड़े तथा सबसे प्राचीन लोकतंत्र है जहां स्वतंत्रता, समानता संविधान के मूल भाग है जिनका उद्देश्य सुभेद्य समूहों को सुरक्षा प्रदान करना है

अन्याय के कारण

1. औपनिवेशिक मानसिकता व विरासत
2. भारत → जातिभेद, लिंगभेद
3. USA → नस्लभेद, लिंगभेद
   → दासप्रथा

सकारात्मक कार्यवाही

1. नागरिक अधिकारों को सर्वाधिक महत्व
2. स्वतंत्रता, समानता संविधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के मूल भाग है

3. Rule of Law को अपनाना
4. मूलाधिकार प्रदान करना
5. संवैधानिक संरक्षण अपनाना।

समानताएँ

1. USA → नस्लभेद, दासप्रथा (गृहयुद्ध पश्चात समाप्ति) की समाप्ति से भारत में Art-17, अस्पृश्यता की समाप्ति।
2. लोकतंत्र को अपनाना।
3. लिखित संविधान
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव की मनाही।
6. धर्मनिरपेक्ष शासन
7. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

एक - दूसरे पर प्रभाव

1. USA के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व लिखित संविधान अपनाना।

Scanned By Camera Scanner

② स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संघीय शासन भारत द्वारा अपनाना।
③ भारत से USA ने महिला मताधिकार ग्रहण किया है।
④ भारत ने USA से procedure Est by law व Due process of Law सीखा है।
⑤ PIL, नागरिक अधिकारों हेतु USA से भारत ने सीखा है।

असमानताएँ

① भारत → आरक्षण, USA में आरक्षण नहीं।
② भारत → जाति-व्यवस्था, USA → नस्लभेद

भारत में प्रदत्त व्यापक नागरिक अधिकारों के कारण भारत न सिर्फ Largest Democracy है बल्कि, ऐतिहासिक परंपरा के कारण "mother of All Democracy" भी है।

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. **(250 words) 15**
संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाल ही में अनेक राज्यों ने स्थानीय ~~आरक्षण~~ Jobs में 75% से लेकर 100% स्थानीय जनता के लिये Jobs को आरक्षित करने के निर्णय लिये हैं।

अधिवास आधारित आरक्षण –

भारतीय संविधान के Article-16 के अनुसार, राज्य सरकार संसद की अनुमति से जरूरत होने पर स्थानीय Jobs में Locals को आरक्षण प्रदान कर सकती है।

समस्याएँ –

① one nation, one market के सिद्धांत को हतोत्साहन
② रिवर्स migration बढ़ा सकती है।
③ भारत में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को बढ़ा सकती है।

Scanned By Camera Scanner

(4) लोक-लुभावन राजनीति का हिस्सा है।

(5) Art-19 के विरुद्ध

(6) Art-16, अवसर की समानता की विरोधी

(7) कंपनियों की लागत ⇑

(8) Ease of doing business को हतोत्साहित करेगी।

(9) Indira साहनी - 50% cap का उल्लंघन

SC का निर्णय

(1) प्रदीप शर्मा case
↳ SC ने, Local क्षेत्र में आरक्षण को गलत प्रवृत्ति माना।

(2) सुनंदा रेड्डी case
↳ Andhra मामले में तेलुगू के आधार पर ज्यादा weightage को असंवैधानिक माना

(3) कैलाशनाथ शर्मा v/s Rajasthan

मामले में भी SC ने इसका समर्थन नहीं किया।

समाधान

(1) Skill Development को प्रोत्साहन
(2) शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना
(3) शिक्षा के अभिन्न हिस्से के रूप में TVET को अपनाना।
(4) कृषि सुधार
- मशीनीकरण ⇑
- महिला स्वामित्व ⇑
- दीर्घकालिक ऋण

(5) MSME को प्रोत्साहन द्वारा शहरी-ग्रामीण gap कम करना
(6) केन्द्र-राज्य समन्वय से विनिर्माण में निवेश हासिल करना।
(7) श्रम सुधार लागू करना।

भारत की व्यापक बेरोजगारी का समाधान आरक्षण न होकर, श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने पर केन्द्रीत होना चाहिये जिससे growth rate में भी वृद्धी हो।

Scanned By Camera Scanner

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? (250 words) 15

ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

ipc की धारा - 124(A) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शब्दों से बोलकर, लिखित या मौखिक रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार को गिराने का प्रयास करता है तो इसे राजद्रोह कहा जाता है।

मुद्दे

① यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है [Art-19]

② इसका प्रयोग अनुचित रूप से पत्रकारों के विरुद्ध (eg विनोद दुआ)

③ यह भारत की UN charter on Human Rights के तहत प्रतिबद्धता के विरुद्ध है।

④ यह औपनिवेशिक विरासत है तथा UK, Australia, NZ ने भी इस प्रकार के कानून समाप्त कर दिये

है।

⑤ राजद्रोह, int. covenant on civil & political right (ICCPR) के विरुद्ध है।

⑥ यह पुलिस राज्य के समान सरकार को शक्ति देता है।

⑦ राजद्रोह का कानून 'innocent until proven guilty' के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

⑧ सरकार द्वारा सिविल समाज एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भी इसका दुरूपयोग का मुद्दा।

⑨ निम्न conviction rate -(2-5%)

समाधान –

① SC ने हाल ही में राजद्रोह कानून के तहत केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है जब तक की सरकार पुनर्विचार नहीं करती है।

② Justice - रोहिंग्टन फली नरीमन ने भी राजद्रोह की समाप्ति का पक्ष लिया है।

Scanned By Camera Scanner

③ 2nd ARC, समाप्त करने का सुझाव दिया है

SC का मंतव्य

① केदारनाथ सिंह केस
- राजद्रोह को वैध माना।
- सरकार को आपात-स्थिति से निपटने में सहायक।
- सरकार को सुरक्षा प्रदान करता है।

② बलवंत सिंह केस
- केवल नारे लगाना देशद्रोह नहीं है

Law commission of India ने कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में ही sedition के उपयोग की सलाह दी है। साथ ही Justice-चंद्रचूड़ ने भी Review की आवश्यकता पर बल दिया है

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. **(250 words) 15**

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

गवर्नमेंट e-मार्केटप्लेस, सरकार द्वारा MSME एवं PSUs से खरीददारी करने हेतु एक online portal है जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

महत्व / सुधार

① सरकारी खरीद की प्रक्रिया को तीव्र बनाया है

② समयबद्ध खरीद सुनिश्चित

③ खरीद में पारदर्शिता↑ — भ्रष्टाचार↓

④ सरकारी खरीद हेतु प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया है

⑤ MSME - 25% खरीद कर, MSME की आर्थिक स्थिति में सुधार

⑥ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

Scanned By Camera Scanner

चुनौतियाँ -

① तकनीक को समय पर update न करना।

② GeM, open source code नहीं है जिससे डाटा सवाल भी उठे है।

③ भुगतान में देरी
(उदा. - MSME को)

④ GeM पोर्टल के संचालन हेतु सरकार के पास कुशल क्षमबल का अभाव है।

⑤ GeM में integrity pact का पालन नहीं हो रहा है।

⑥ GeM के माध्यम से खरीद में गुणवत्ता जाँच हेतु निश्चित प्रक्रिया व विशेषज्ञता का अभाव

⑦ GeM

समाधान -

① PPP mode में GeM की तकनीकी को update करना।

② GeM को open source code बनाना।

③ खरीददारी में integrity pact लागू करना।

④ National policy for public procurement का पालन करना

⑤ खरीददारी में सभी के लिये समान अवसर सुनिश्चित करना।

⑥ सरकारी क्षमता निर्माण करना।

⑦

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. (250 words) 15
अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत में सिविल सेवाए औपनिवेशिक शासन की देन है जिन्हे 'steel frame of India' कहा जाता था परंतु, वर्तमान में ये समस्या से ग्रस्त है

आवश्यकता -

(1) सिविल सेवाओं को Rules based से Result oriented बनाने हेतु
(2) Active से proactive बनाने हेतु
(3) सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता हेतु
(4) सिविल सेवकों को policy निर्माण (Administrative Adjudication) तथा प्रशासनिक न्याय-प्रदायगी में भागीदारी हेतु [323]- tribunals
(5) सिविल सेवाओं को unlimited से Limited जिम्मेदारी प्रदान करने हेतु

1835
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) Controller से facilitator बनाने के लिये
(7) औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने हेतु (पेन्चप्रन)

सुधार

(1) भर्ती के स्तर पर
- → भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करना (PCS exams में)
- → भर्ती को समयबद्ध करना (PCS, निश्चित कैलेण्डर नहीं)
- → व्यापक vacancies को भरना (उदा.- पुलिस में)
- → विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों से
- → training प्रक्रिया में सुधार
- → multi-skill बनाना
- → तकनीकी के उपयोग संबंधी क्षमता की जाँच करना

(2) प्रशिक्षण
- → भर्ती के दौरान
- → सर्विस के दौरान नियमित रूप से (iGOT - कर्मयोगी प्लेटफार्म से)
- → global norms अपनाना - gender संवेदनशीलता ↑

↳ online प्रशिक्षण को प्रोत्साहन
↳ on-sight learning को प्रोत्साहन

मूल्यांकन

① सर्विस में समय-समय पर मूल्यांकन करना (5 yr, 10 yr, 15 yr, 20 yr)

② Art-310, 311 को क्रमिक रूप से समाप्त करना।

③ मूल्यांकन का पारदर्शी ढाँचा

④ अकर्मण्य सिविल सेवकों को VRS के माध्यम से समय पूर्व Retirement

⑤ promotion को performance से जोड़ना

सिविल सेवाओं में व्यापक सुधार हेतु DOPT ने हाल ही में 'National civil services training institute' में सुधार हेतु guidelines जारी की है

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. (250 words) 15

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत में शिक्षा में व्याप्त शहरी-ग्रामीण तथा लैंगिक अंतराल को प्रथम NGO द्वारा जारी ASER रिपोर्ट मे खुलासा किया है

निर्धारित लक्ष्य

① प्राथमिक शिक्षा - 100% नामांकन

② माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को Double करना

③ उच्च शिक्षा में नामांकन दर 50% प्राप्त करना (NEP, 2020)

④ लर्निंग poverty समाप्त करना

⑤ STEM में women भागीदारी ↑

सरकारी पहलें

① NEP, 2020
↳ शिक्षा पर व्यय GDP-6% तक करना

- Higher education commission of India की स्थापना
- 5+3+3+4 पेटर्न
- शिक्षा + skill Dev. को प्रोत्साहन
- special education zones की स्थापना
- PM- दीक्षा पोर्टल
- स्वयं-प्रभा पोर्टल
- NPTL

उन सभी पहलों के बावजूद UNESCO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापक Learning Poverty व्याप्त है जिसे Covid-19 ने बढ़ा दिया है।

कारण

① Digital Device
- शहरी - ग्रामीण अंतराल
- निजी - सरकारी स्कूल अंतराल
- gender gap < male / female

② कुपोषण की व्यापकता (NFHS-5)
③ रटने पर ज्यादा focus
④ शिक्षा में skill Dev. का अभाव
⑤ शिक्षा का रोजगारोन्मुखी न होना (employbility - 49%)
⑥ Infra का अभाव, जिससे Girls माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में निम्न नामांकन

समाधान -

① PPP mode < Byju / unAcademy के साथ सहयोग (NITI Aayog MoU)
② ग्रामीण school में infra सुधार करना (15th F.C. - special fund)
③ शिक्षा में सीखने पर बल
④ PM- पोषण शक्ति (अंडे, मीट शामिल करना)

अधिगम poverty समाप्त करके ही भारत कुशल workforce का निर्माण कर सकता है जो 2018-55, 37 वर्ष के Demographic Divident का use करने में महत्वपूर्ण होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. (250 words) 15

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत में प्रायः संचारी रोगों पर वर्तमान में ज्यादा बल दिया जा रहा है (covid के काल) परंतु, 60% से ज्यादा ~~मौतें~~ मौते तो NCDs के कारण ही हो रही है

सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, रोगों को समयपूर्व पहचाने या उनकी संभावना को पहचानने की प्रक्रिया है।

आवश्यकता

① संचारी रोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि
उदा. - Covid-19, Lumpy skin डिसीज

② one health अप्रोच का दृष्टिकोण अपनाने हेतु

③ रोग प्रबंधन हेतु एकीकृत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दृष्टिकोण के लिये।

④ infra मुख्यतः शहरों में होना

⑤ स्वास्थ्य प्रणाली का preventive की बजाय curative होना

⑥ WASH पर कम फोकस

⑦ व्यापक गरीबी तथा out of pocket expenditure - 60% होना।

चुनौतियाँ

① Health state subject
↳ केन्द्र - राज्य पर्याप्त समन्वय का अभाव

② राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति तथा राजकोषीय व्यय

③ health Data के रखरखाव की चुनौती।

④ Quality युक्त, Health Data का अभाव

⑤ Health Labs का उचित - रखरखाव नहीं

⑥ CHC, PHC तथा sub-Center

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से Data collection क्षेत्र न होना

सरकारी प्रयास व समाधान

1. one health अप्रोच अपनाना
2. National digital health mission
3. नीति आयोग - Health सर्विलांस पर white paper
4. integrated health infor portal
5. ICMR के तहत 100+ Labs की राष्ट्रीय चैन
6. WHO - बॉयोहब में शामिल होना

सरकार को डिजिटल India के माध्यम से online Health Data के रखरखाव हेतु skill dev करते हुये National Data Policy पर विचार करना सुरक्षा चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis. **(250 words) 15**

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

श्रीलंका की सरकारों की freebies policy तथा असतत आर्थिक निर्णयों एवं covid-19 की मार से tourism पर प्रभाव के कारण श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

संकट के कारण

1. china से असतत ऋण
2. tourism पर covid-19 के कारण, विदेशी मुद्रा ↓
3. अचानक से organic farming पर shift होना
4. लोकलुभावन राजनीति

भारत पर प्रभाव -

1. श्रीलंका का आर्थिक संकट, श्रीलंका

Scanned By Camera Scanner

के गृहयुद्ध को पुनः जीवित कर सकता है जिससे भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव।

② श्रीलंका से शरणार्थियों का भारत आना, शरणार्थी समस्या को बढ़ावा।

③ तमिल मूल के श्रीलंकन तथा सिंघली के संघर्ष पर तमिलनाडु जैसे राज्यों को साथ लेकर चलने की चुनौती।

④ आतंकवाद, चरमपंथ एवं समुद्री डकैती को प्रोत्साहन।

⑤ विदेशी हस्तक्षेप, मुख्यतः चीन का प्रभाव बढ़ा सकता है।

⑥ भारत की आर्थिक सहायता प्रदान करने की सीमित क्षमता, विश्वास को कम कर सकती है।

⑦ श्रीलंका में military शासन

राजनीतिक अस्थिरता व मानवाधिकार संकट का कारण बन सकता है।

⑧ राजनीतिक सुधारों (मुख्यतः विकेन्द्रीकरण) को टाल सकता है।

भारतीय कदम

① भारत ने chemical fertilizers प्रदान किया है।

② petrol-diesel supply द्वारा लंका में fuel shortage ↓

③ essential medicine प्रदान कर hospitals को सुचारू रखा है।

④ $ 3.5 bn की कुल सहायता

⑤ ऋण भुगतान को सस्पेंड किया है।

⑥ IMF से वार्ता हेतु, विशेषज्ञ सहायता।

⑦ Japan-USA के साथ मिलकर, Debt-swap तथा currency swap Agreement।

IMF श्रीलंका को $ 2.9bn की सहायता हेतु समझौता किया है परंतु, व्यापक economic reforms तथा economy के विविधीकरण बिना संकट का समाधान संभव नहीं है।

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss.

(250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

हिन्द महासागर अपने geo-political तथा geo-economic महत्व के कारण, वैश्विक शक्तियों हेतु नये रणक्षेत्र के रूप में उभरा है, भारत की केन्द्रीय स्थिति, भारत की इस क्षेत्र में भागीदारी प्रोत्साहित करती है।

भारत की भागीदारी

1. Quad के साथ भागीदारी
2. Indo-pacific economic framework में शामिल होना
3. Asean के साथ FTA
4. SAARC, BIMSTECH समूह में भागीदारी
5. IORA, Indian ocean comm. में भारतीय भागीदारी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत इस क्षेत्र में Net security प्रदाता की भूमिका निभा सकता है-

1. चीन के बाद इस क्षेत्र में सबसे बड़ी Navy है
2. Quad के साथ सहयोग
3. हिन्द महासागर < लक्षद्वीप / A&N द्वीप समूह, रणनीतिक स्थिति
4. चाबहार port का रणनीतिक महत्व।
5. JAI ग्रुप में, जापान-आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग
6. china को counter करने हेतु Asean < वियतनाम / फिलीपींस के साथ सहयोग
7. प्राकृतिक आपदाओं में HADR प्रदाता (उदा.- operation < नीर / वनीला)
8. मारिशस, मालदीव छोटे देशों को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।

Scanned By Camera Scanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

China
- Debt trap policy
- String of pearls policy

- भारत की Quad भागीदारी पर संशय
- AUKUS, भारत का महत्व कम करेगा

समाधान

1. Defence budget के 15% से 30% तक Navy पर व्यय ↑
2. INS विक्रांत के समान अन्य IAC निर्माण।
3. सिडनी डायलाग, कोलंबो डायलॉग के माध्यम से भागीदारी
4. I2U2 का use, तकनीकी उन्नयन में
5. EU, USA, AUKUS के साथ सैन्य समझौते करना, जिससे शक्ति संतुलन हो।

भारत की Indo-pacific भागीदारी freedom of Navigation तथा free & open, Indo-pacific के उद्देश्य से संचालित है।